म.प्र. में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ और नई दृष्टि की आवश्यकता

[सेमेस्टर प्रणाली के प्ररिप्रेक्ष्य में]

* डॉ. लक्ष्मण परवाल, ** श्रीमती अरविन्दर कौर

राष्ट्र की प्रगति में उच्च शिक्षा की उल्लेखनीय भूमिका होती है। स्वतंत्रता के 62 वर्षों के बाद हम उच्च शिक्षा की प्रगति पर दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होगा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा के स्तर में प्रगति के साथ शिक्षा के स्तर में गिरावट भी आई है, फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नई उच्च टेक्नालॉजी, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। भावी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए कई उपयोगी व महत्त्वपूर्ण योजना बनाने व क्रियान्वित करने की नीतियां बनाई गई हैं, उसमें असफलता अधिक मिली है। इसके परिणामस्वरूप आज शिक्षा का स्वरूप ऐसा उद्घाटित होता है जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विद्यार्थी को कोई रोजगारोन्मुखी शिक्षा सुविधा नहीं है। इससे स्थिति ऐसी बन गई है कि अब उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्ति इतनी महंगी होती जा रही है कि तकनीकी, इंजीनियरिंग , मेंडिकल, प्रबंध, कम्प्यूटर क्षेत्रों में अध्ययन करना तो दूर की बात है, इसमें प्रवेश लेना ही असंभव हो रहा है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति न तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है और न हीं शोधकर्ताओं को उचित स्तरीय सामग्री उपलब्ध करा रही है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नैतिक मनोबल गिर रहा है। वे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 62 वर्षों पर गौर करें कि हमने किन क्षेत्रों में प्रगति कि और किन क्षेत्रों में गिरावट आई तो तस्वीर इस प्रकार दिखाई देती है।

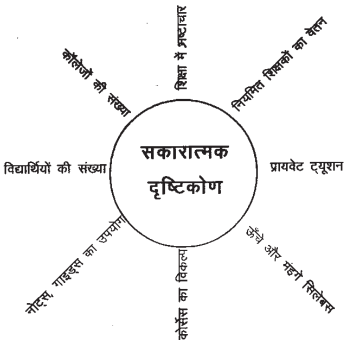

उपर्युक्त सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात तो काफी समय से की जा रही थी परन्तु इस दिशा में सार्थक पहल करने का एक नया प्रयास पहली बार मध्यप्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने किया है। वर्ष 2008–09 से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेंस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करने, सुव्यक्तिकरण एवं चिंतन हेतु सक्षम बनाना इस प्रणाली के उद्देश्य हैं। प्रथम सेमेंस्टर पूर्ण होने के पश्चात् इसमें जो कमियां/चुनौतियां दिखाई दे रहीं है वे इस प्रकार हैं :–

■ उच्च शिक्षण संस्थाओं की सतत् मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। ■ कार्य के प्रति लापरवाह व्यक्तियों के लिये उचित दण्ड का प्रावधान नहीं है। ■ कार्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के लिये उचित पुरस्कार या प्रमोशन देने का नियमानुसार उचित समयावधि में प्रावधान नहीं है। ■ प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थाओं में खाली रिक्त पडे पदों पर शीघ्रता से (स्थायी) भर्ती या स्थानांतरण के माध्यम से रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये ठोस प्रक्रिया/नियम नहीं है। ■ उच्च शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों (शिक्षक, कार्यालयीन स्टॉफ, कमरों, फर्नीचर, किताबों, उपकरणों) के अनुपात से विद्यार्थियों के प्रवेश के नियम नहीं हैं। ■ सेमेंस्टर सिस्टम को रोजगार व स्वरोजगारमुखी बनाने के प्रयासों में, पाठ्यक्रमों में, कम्प्यूटर शिक्षा व रिसर्च मेंथ्डोलॉजी की शिक्षा की अनिवार्यता शामिल नहीं की गई है। ■ शिक्षकों को नवाचार से जोड़ने हेतु वार्षिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान नहीं है। ■ संस्था प्रमुख सभी कार्यक्षेत्रों में अपने कर्त्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग नहीं होने से संस्था को प्रगतिशील बनाने में सहायक नहीं हो पा रहे हैं। ■ स्थानीय राजनीति (सांसद, विधायक, जनभागीदारी अध्यक्ष व सदस्यगण, छात्र संगठन, अन्य) के दबावों के कारण भी संस्था प्रमुख अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते है। ■ कक्षाओं में उपस्थिति नहीं बढ़ना भी एक प्रमुख समस्या है। कक्षाओं में उपस्थिति नहीं होने से अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों (एन.एस.एस./एन.सी.सी/क्रीड़ा/युवाउत्सव/साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों) में

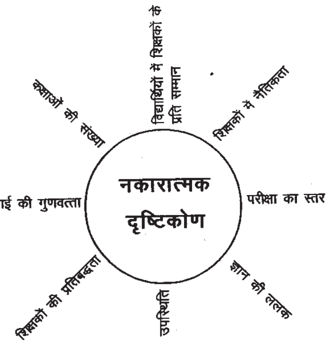

* सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
** अतिथि सह.प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, नागदा (म.प्र.)

शून्यता का भाव दिखाई दे रहा है। ■ विद्यार्थियों की उपस्थिति का सही दर्पण बनाने में संस्था प्रमुख अपने अधीनस्थों को उचित मार्गदर्शन देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर सभी शिक्षण संस्थाएं भी इस समस्या पर एकमत नहीं है। कम उपस्थिति की द ा में छात्रवृत्ति प्रदाय करना/नहीं करना भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। ■ शिक्षक वर्ग भी शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उलझे रहने से शिक्षा के मूल उद्देश्य से दूर होते जा रहे हैं। वे चाहकर भी अन्य कार्यों को समयावधि में पूरा करने की होड में अपने विषय का अध्ययन–अध्यापन नहीं करा पाते हैं। ■ शिक्षकों को नवाचार से जोड़ने एवं उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण के लिये भेजने में संस्था प्रमुख द्वारा भी उत्सुकता व तत्परता दिखाई नहीं देती है। साथ ही संस्था के नीतिगत फैसलों में सभी शिक्षकों की राय न लेकर अपनी पसंद के शिक्षकों से ही परामर्श करके संस्था को चलाने का प्रयास किया जाता है।

भारतीय उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में (मध्यप्रदेश में लागू सेमेंस्टर प्रणाली सहित) आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे कि यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकुल हो जाये। साथ ही शिक्षा के स्तर में बड़े पैमाने पर उन्नति हो सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इसके लिये उच्च शिक्षा में नई दृष्टि की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है :–

★ प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की सतत् मानीटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । यह मानीटरिंग व्यवस्था जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किसी गोपनीय विभाग से कराई जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हों। ★ प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करके उन्हें भरा जाना चाहिए। जिन संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक स्टॉफ हो उन्हें वहाँ से कार्यमुक्त करके अन्य संस्थानों में जहाँ उनकी आवश्यकता हो वहाँ पदस्थ किया जाना चाहिए। ★ उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश वहाँ उपलब्ध संसाधनों (शिक्षक, कार्यालयीन स्टॉफ, फर्नीचर, कमरों, किताबों, उपकरणों) के आधार पर होने चाहिये। इसमें उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित संख्या के अनुपात में बिना आरक्षण के प्रवेश की पात्रता होनी चाहिये, शेष विद्यार्थियों के लिये स्वाध यायी/पत्राचार/ओपन परीक्षा के माध्यम से अध्यापन कराने की व्यवस्था होनी चाहिये। ★ सेमेंस्टर प्रणाली में लागू की गई सतत् आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को निरंतर जारी रखा जाना चाहिये, किन्तु इसमें प्रारंभ की गई कुल 12 विद्याओं में से प्रत्येक शिक्षण संस्था को अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार 06 विधाओं को अपनाये जाने का विकल्प होना चाहिए। ★ सेमेंस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेंस्टरों में कम्प्यूटर शिक्षा व रिसर्च मेंथ्डोलॉजी की शिक्षा अनिवार्यतः शामिल की जानी चाहिये, जिससे कि विद्यार्थियों को सेमेंस्टरों में उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट बनाने में निपूणता प्राप्त हो सके। ★ सेमेंस्टर प्रणाली में प्रोजेक्ट कार्य स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के तीसरे सेमेंस्टर में संस्था स्तर पर ही चुने गये विषय पर तथा तृतीय वर्ष के पाँचवे सेमेंस्टर में संस्था के बाहर तीन माह का तकनीकी या रोजगारोन्मुखी प्रोजेक्ट होना चाहिये। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेंस्टर में संस्था स्तर पर ही चुने गये विषय पर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेंस्टर में संस्था के बाहर रहकर किसी भी रोजगार प्रदाय करने वाली कम्पनी में लगभग 3 से 6 माह का होना चाहिये।

★ सेमेंस्टर प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिये जो 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को पूरा कर सकते हों, इसके लिये प्रवेश के समय विद्यार्थियों व अभिभावकों से एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिये जिससे वे वचनबद्ध हो सके की उपस्थिति का पालन नियमानुसार करेंगे। ★ शिक्षक वर्ग को भी नवाचार से जोड़ते हुए कम्प्यूटर व रिसर्च से संबंधित वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन स्तर पर की जानी चाहिये। ★ उच्च शिक्षण संस्थाओं में क्रीड़ा अधिकारी / ग्रंथपाल की तरह ही एन.सी. सी./एन.एस.एस. की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इन पदों पर भी संबंधित अधिकारियों की पूर्ण रूपेण नियुक्तियाँ शासन स्तर की जानी चाहिये। तभी शासन की मंशानुसार विद्यार्थियों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की संकल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सकेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्था प्रमुख पदों पर नियुक्तियां सेना के रिटायर्ड कर्नल व मेंजर जैसे व्यक्तित्व को दी जानी चाहिये, जिससे कि वे शासन व संस्था के हित में शिक्षा की मर्यादा के अनुरूप कड़े अनुशासन व नियमों का पालन करते हुए शिक्षा संस्थाओं को बिना किसी राजनैतिक दबाव के संचालित कर सके। ★ शिक्षा की सर्वांगीणता को साकार करने के लिये उसमें आध्यात्मिक पक्षों को भी शामिल किया जाना चाहिये, यह वर्तमान समय की पुकार है, आवश्यकता है। यह भारतीय सनातन संस्कृति का अमूल्य रत्न है, जिसका अनुसरण विकसित पश्चिमी देश भी करने लगे हैं।

निष्कर्ष :–उपरोक्त परिवर्तनों को एक साथ शैक्षिक तथा सामाजिक रूपांतरण की कोशिश में तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक हम इन परिवर्तनों के समर्थन में जन–जागृति को विकसित नहीं करेंगे और स्वयं लोगों को इन कार्यक्रमों के साथ नहीं जोड़ेंगे। राष्ट्रव्यापी जन–जागृति लोगों की शैक्षिक उन्नति और राष्ट्रीय विकास के लिये अपरिहार्य होती है। उच्च शिक्षा सुधार केवल भाशण श्रृंखला अथवा योजना व्यय में वृद्धि से संभव नहीं है, इसके लिये कार्यशैली में रचनात्मक परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को इसे गंभीरता से लेना होगा, तभी माँ सरस्वती के मंदिर की रक्षा होगी।

सन्दर्भ–1. भाई योगेन्द्रजीत : शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियाँ, विनोद पुस्तक मंदिर, हॉस्पिटल रोड़, आगरा–3 (नवीनतम संस्करण) 2. डॉ.बी.बी.अग्रवाल : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं विनोद पुस्तक मंदिर, हॉस्पिटल रोड़, आगरा– 3 (नवीनतम संस्करण) 3. ''कुरूक्षेत्र '' मासिक पत्रिका, नई दिल्ली के विभिन्न संस्करण। 4. ''योजना '' मासिक पत्रिका, नई दिल्ली के विभिन्न संस्करण। 5. दैनिक भास्कर, नईदुनिया इन्दौर के विभिन्न संस्करण।